STATUTORY RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF CONTINUANCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO MANIPUR

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): Madam, I beg to move the following resolution:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 31st December, 1993, under article 356 of the Constitution of India in relation to the State of Manipur, for a further period of six months with effect from the 30th June, 1994."

As the House is aware, the President issued a proclamation under article 356 of the Constitution imposing President's Rule in Manipur. The Legislative Assembly of the State is presently under suspended animation. The proclamation, as approved by both Houses of Parliament on 22.2.94, shall cease to operate on the expiration of a period of six months from the date of issue of the proclamation, that is, on 29.6.94.

The Governor of Manipur in a recent report has stated that the overall law and order situation in the State has shown steady improvement for the last four months. The Naga-Kuki conflict is firmly under control though it is as yet delicately balanced in sensitive areas. This conflict is likely to resurface in case of any let up in security operations. The violent activities by the Mitei Extremists and Naga-Kuki insurgents continue to be and are likely to remain on a high level for some more time to come.

The Governor has reported that on the development side, the reprivatisation of essential schemes relating to roads, water supply, irrigation, medical and public health and education has been done and adequate funds have been allotted to the development departments. The public distribution system has also been streamlined, particularly in the hill areas. The availability of rice, wheat and kerosene has been augmented.

While the efforts to contain extremists on the one hand and the revival of development activities on the other, have gathered momentum, the Governor is of the opinion that the improvement of overall security environment, neutralisation of parochial and vested interests, achieving tangible results in the developmental field and improving the morale of the administration and police will require sustained efforts for a minimum period of another six months.

In the circumstances, the Governor has recommended that the Proclamation dated 31.12.1993 under article 356 of the Constitution may be extended for a further period of six months.

On its part, the Central Government, would, continue to assist the State administration in containment of extremist activity as well as in its efforts to increase the pace of development. The situation in Manipur is hoing continuously and closely monitered by the Central Government.

Keeping in view the situation prevailing in the State and taking all the relevant factors into consideration, it is proposed that the President's Rule in Manipur may be continued for a further period of six months w.e.f. the 30th June, 1994.

In view of the position explained by me, I solicit the approval of this august House to the Resolution.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): There is an amendment by Shri Satya Prakash Malaviya.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Madam, I beg to move:

> "That in the said Resolution for the words "six months", the words "three months" be substituted."

The question was proposed.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करते समय धारा 356 के तहत किसी राज्य की चुनी हुई सरकार को भंग करने अथवा विधानसभा को निलंबित करने का अधिकार बड़ा ही सीमित रखा था और संविधान निर्माताओं की ये भावना थी कि लोकतंत्र की बहाली और लोकतंत्र की पुष्टि के लिए चुनी हुई सरकारों को भंग नहीं करना चाहिए और न ही विधानसभा को निलंबित करना चाहिए।

महोदया, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब से हमारे देश का संविधान लागू हुआ, लगभग 90 मर्तबा राष्ट्रपति शासन की विभिन्न राज्यों में उद्घोषणा हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले और सरकारें बनाने से पहले क्या उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है कि जो भी सरकार निर्मित होने वाली है, क्या यह टिकाऊ सरकार होगी? क्या यह संविधान के अनुसार कार्य कर सकेगी? क्या ये राज्य की समस्याओं का समाधान कर सकेगी? क्या इन बिंदुओं का मूल्यांकन किया जाता है? यदि नहीं किया जाता है तो फिर सरकार भंग करने की आवश्यकता पड़ती है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि ये मणिपुर की सरकार, जिसका नेतृत्व श्री दौरेन्द्र सिंह कर रहे थे, चूंकि ये कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए क्या भारत सरकार को या कांग्रेस पार्टी को यह नहीं मालूम था कि यह सरकार टिकाऊ नहीं है? यह सरकार चलाऊ नहीं है और यह सरकार राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती।

महोदया, दौरेन्द्र सिंह पहले भी मुख्य मंत्री रह चुके थे। इनके नेतृत्व में मणिपुर में पहले भी कांग्रेस का राज्य रहा था। लेकिन जिस नागा उग्रवादी संगठन को कुचलने में ये नाकामयाब रहे थे, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन को मुख्य मंत्री पद से हटाया था और इन को राजनीतिक वनवास दे दिया गया था, पांच साल तक इनको सभा में नहीं आने दिया था, क्या कांग्रेस के लोग इस बात को भूल गए थे कि जो व्यक्ति एक बार निकम्मा साबित हो गया है और आज वहां बगावत कर रहे नागाओं से उनका रिश्ता है, वह नागाओं के एक ग्रुप से संबंधित है, इसीलिए उन को हटाया गया था, तो फिर इन को मुख्य मंत्री बनाने की आवश्यकता क्या थी? क्यों उन को प्रदेश का राज्य सौंपने की आवश्यकता पड़ी? साथ ही साथ जो इनके डिप्टी कहे जाते हैं घीसिंग, जो दूसरे नागा नेता हैं, वह भी एक उग्रवादी संगठन से संबंधित हैं, ये उनके साथ थे और दोनों ही जब नाकामयाब रहे तो इनके हाथ में सत्ता सौंपने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद यह तो एक पक्ष है कि आप ने वहां पर सड़क निर्माण का काम किया है, पानी दिया है, आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही किया है, लेकिन वहां पर एक टिकाऊ सरकार बनकर चल सके, क्या इस का भी आपने मूल्यांकन किया है? क्या आपने कांग्रेस पार्टी का पुनर्गठन किया है? क्या कांग्रेस के लोगों को आपने एकमत किया है? क्या दौरेन्द्रसिंह और घीसिंग जो एक मिशन और एक मत के हैं, क्या प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इन दोनों नेताओं का समर्थन करती है? वहां जो चुने हुए विधायक हैं वे उन को समर्थन देते हैं? वहां की कांग्रेस पार्टी उन को समर्थन देती है और अगर नहीं देती है तो फिर यह सरकार कैसे चला सकेंगे?

महोदया, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जनवरी 1995 या अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और जब चुनाव होने वाले हैं तो इन विधान सभा को निलंबित क्यों रखा है उन चुनावों को आप पहले भी करा सकते हैं। तो उस राज्य के ऊपर इतना बड़ा बोझ पैसे का, जो तमाम विधायकों की तनख्वाह में जा रहा है, आपने क्यों लाद रखा है? इससे अच्छा तो यह होगा कि वहां की विधान सभा को भंग कर दिया जाए। जनवरी में या सारे देश के अंदर जब 8-10 राज्यों में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं तो आप मणिपुर में भी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव करा सकते थे। आप को विधान सभा को निलंबित रखने की क्या आवश्यकता है?

महोदया, मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे आपने इतना बड़ा बोझ, इतनी बड़ी फिजूलखर्ची उस राज्य सरकार के ऊपर डाल रखी है? यह पैसा जो विधायकों की तनख्वाहों पर चला जाएगा, अगर यह पैसा आप वहां के निर्माण के कार्यों में लगाते तो लोगों को कुछ राहत मिलती। आप ने निलंबन में विधान सभा को क्यों रखा है? क्यों आप राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना चाहते हैं?

महोदया, दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह बगावत की भावना क्यों पैदा होती है? आप को मालूम है कि नागाओं की पहले से ही अपनी एक मंशा यह रही है उन की जो संस्था है एन०एस०सी०एन० की मंशा

[श्री संघ प्रिय गौतम]

यह रही कि जो म्यांमार से बार्डर लगती है इस पर नागा कब्जा जमा लें। चूंकि वहां पर कूकी लोग बहुत हैं जो कभी तत्कालीन बर्मा से विस्थापित हो कर यहां पलायन करके आए थे, उन की संख्या कम है, वह जंगलों में और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, वह इतने शक्तिशाली भी नहीं हैं जितने की नागा हैं, तो आप ने उनकी रक्षा की क्या व्यवस्था की है? जो कूकी हैं उन के लिए आपने डिफेंस की, सुरक्षा की कोई स्कीम बनाई है। क्या आपने पैरा-मिलिटरी फोर्सेज वहां पर लगाई हैं? क्या आप ने मोरे टाउन और जो नेशनल हाईवे नंबर 39 है, इसकी स्थायी व्यवस्था आप ने की है? जो इन नागा उग्रवादियों के हाथों में, उनके कब्जे में न आ सके? क्योंकि वह मोरे कस्बा जो है जो आपका अवैधानिक ट्रेड का अड्डा है वह उनका स्मगलिंग का अड्डा भी है। सारी लड़ाई इन नागा उग्रवादियों की जो बगावत पर उतरे हैं, मोरे टाउन पर कब्जा करने की है। यह जो बार्डर है इस पर कब्जा करने की रही है। उनके मन्सूबे अभी खत्म नहीं हुए हैं। आपने जो राष्ट्रपति शासन लागू किया था आपको मालूम था अगस्त के महीने में सैकड़ों आदमी नागा और कूकी दोनों के संघर्ष में मारे गये थे, आपने उस समय राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया था। 31 दिसम्बर, 93 को क्यों राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? क्योंकि 11 नागा विधायकों को बगावत करने वाले नेताओं का संदेश आ चुका था कि आप इस्तीफा दे दीजिए सरकार से और नहीं देंगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। आपने उन परिस्थितियों के कारण यह किया। मजबूरी में आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया। क्योंकि 11 नागा सरकार से इस्तीफा दे देते तो दौरेन सिंह की सरकार वैसे भी गिर जाती। आपकी नीयत अच्छी नहीं थी। मैं गृह मंत्री जी आप से कहना चाहूंगा कि यह तो हमारी मजबूरी है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक वहां पर राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी इसलिए मजबूर होकर हम आपका समर्थन करेंगे, आपको स्वीकृति भी देंगे और राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ानी होगी लेकिन इसके पीछे आपने कोई प्रयास नहीं किया है। केवल इतना कह देना कि हमने इस सिस्टम को ठीक कर दिया है, यह उचित नहीं है। सिस्टम तो यह है कि रोजगार आपने वहां पर मुहैया नहीं कराये है इस कारण वहां के नौजवानों में असंतोष व्याप्त है। राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाये इसलिए वह भी वहां अभी तक व्याप्त है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाये वह भी आज वहां व्याप्त है। इस सब का उल्लेख आपने अपने वक्तव्य में कतई नहीं किया है। इसके अलावा आपने बताया कि जो उग्रवादी हैं, जिनको वहां फोर्सेज पकड़ कर ले जाती है या जो सरैण्डर करते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की आपने कोई योजना नहीं बनाई है तो कैसे आप उनके असंतोष को दूर करेंगे। इन तथ्यों का आपने उल्लेख नहीं किया। जब तक गृह मंत्री जी मणिपुर के लोगों को काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा जो बेकार लोग हैं या जिन लोगों ने सैरण्डर किया है उनको आप रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे, राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर नहीं करेंगे, प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दूर नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी को संगठित नहीं करेंगे और दौरेन्द्र सिंह और घीसिंग को वहां की कांग्रेस पार्टी एक जगह बैठाकर मेल नहीं कराती है तो 6 महीने के बाद आप फिर आयेंगे। आपको दुबारा राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ाने के लिए अवश्य आना पड़ेगा। इसलिए आप से यह कहता हूं कि आप यहां पर घोषणा कीजिए और हमें बताइये कि हमने ये-ये कदम, जिनका मैंने उल्लेख किया है, उनके हल के लिए, उनके समाधान के लिए उठाये हैं। हम अक्तूबर या नवम्बर में वहां पर विधान सभा का चुनाव करा देंगे। वहां पर आज जो वर्तमान विधायकों की स्थिति है, विभिन्न दलों की जो स्थिति है उससे कोई टिकाऊ सरकार चलने वाली नहीं है। जो तत्कालीन मुख्य मंत्री और उसके डिपुटी हैं वे खुद वहां पर बगावत करने वालों के साथ मिले हुए हैं। उनके बहकावे में है। वे वहां पर सरकार नहीं चला सकते। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कृपा करके वहां पर स्थिति को मजबूत कीजिए और कूकीज की हिफाजत कीजिए। वहां पर उनकी आबादी कम है इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए उनको हथियार या उनको अपनी सुरक्षा के लिए कोई साधन मुहैय्या कराइये, उनकी हिफाजत के लिए पैरा मिलिटरी फोर्स लगाइये और अपनी पार्टी को कांफिडेंस में लेकर वहां पर मजबूती लाइये। यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur): Madam Vice-Chairman, I thank you very much for giving me this opportunity to say something regarding Manipur.

Madam, I do not vehemently oppose this Statutory Resolution now, moved by the hon. Home Minister nor can I straightway endorse this measure. There are certain peculiar situations prevailing over there. Manipur is in a very bad shape now. On 22nd February, when the

Presidential Proclamation was brought forward in this august House for approval, I whole-heartedly supported the Resolution. And I frankly admitted that in the past one month and 23 days since President's rule was imposed, there was a slight improvement in the overall situation. I put it as 20 per cent improvement in the situation. So, in the first two months of President's Rule, the situation was improving. But, thereafter, the improvement drained and the situation prevailed as usual. So, I cannot say that the Presidential Proclamation should be lifted. That is not our intention. All that we wanted was that President's Rule should not be too long. That was our wish. We thought that the insurgent activities and the law and order situation would be curbed effectively. Even though the situation in Manipur is really bad, yet it is not as bad as the situation prevailing in Kashmir and other terrorist-infested areas. Now, if a little more importance and attention had been paid to the State of Manipur, then curbing of insurgency and improvement of the law and order situation would not have been a very difficult task. Now, I fully support the hon. Home Minister's data about the law and order situation prevailing there. But it is because of the political system, the unfortunate political frame of mind of the local leaders of the then ruling party over there, that the situation aggravated. I would like to quote a few lines from the Governor's Report on the imposition of President's Rule. Some of the ruling party Members in the State have insinuated that Kulabidhu Singh was a supporter of the Governor. I am not a supporter of the Governor. But I would like to say that a very true picture has been drawn, that factual ground realities have been mentioned, by the Governor. Since it convinces me, I should endorse his move and I do support it. But it does not mean that I am supporting the Governor, Mr. V.K. Nair. I am not supporting him as an individual. But when he gives certain figures, ground realities, they should be appreciated by everybody concerned. So, it is not that Kulabidhu Singh is a supporter of the Governor. Now, in this connection, I may quote a few lines from page 2 of the Governor's Report, that portion which relates to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Finance Minister, Tribal Development Minister and Power Minister. I do not want to name them, but their designations clearly indicate who those persons are. So, there is no harm in mentioning their names even. The Chief Minister was Mr. R.K. Dorendra Singh; the Deputy Chief Minister was Mr. Rishang Kishing; the Finance Minister was Mr. C. Dougel; the Power Minister was Mr. Holkhomang Haokip and the Tribal Development Minister was Mr. Morung Mokunga. Two of them are Nagas, two of them are Kukis and Mr. R.K. Dorendra Singh is a Meitei. When these important Ministers--the Chief Minister and the Deputy Chief Minister--have got links with insurgent groups, this is a very horrible, terrible affair. The Governor at page 2 of his report says and I quote:

> "....Shri Rishang Keishing is in open revolt against the Chief Minister. The Chief Minister has not only failed to discipline him, but by his inaction, left the field free for Rishang Keishing to carry out his evil design of aiding and abetting the NSCN (I-M) and subvert the Government machinery and the police. Shri Rishang has also precipitated the Naga-Kuki conflict and gave it the colour of an ethnic conflict. The Chief Minister himself is suspected of aiding a faction of the Meitei extremists...."

In this way, the mischief is created by the ruling party people. This terrible condition in Manipur is their own mischief. Now, I would like to mention about the role of the Ministers and other MLAs. A reference was made by the Governor at page 3 of his report. The Governor said something about the change in the leadership. the PCC

[Shri W. Kulabidhu Singh]

President wants a change in the leadership. He did not want Mr. R.K. Dorendra Singh to continue as the Chief Minister. Regarding change of leadership, I also endorsed the view of the Governor. In his report of page 3 the Governor stated and I quote:

> "....In my opinion, in the conditions prevailing in Manipur at present, the real issue is not of the change in leadership or of alternatives but to find an end to periodic manipulations for power by different groups or individuals as this has resulted in lack of political direction to the Government and guidance to the administration...."

In this way, unfortunately, these so-called leaders of the ruling party in the State of Manipur are bungling. Their main aim is to retain power and earn money, not about any development activity and something of that sort. They don't think of how to develop the State. Even the money granted by the Central Government, sanctioned by the Central Government, remains unutilised because this money is allocated by the Central Government and swindling or looting of this money may not be possible. So, they don't consider about the development of the State. The only thing they consider is about earning some money, looting the public money.

Another factor affecting the law and order situation is the NSCN activity, the National Socialist Council of Nagaland (I-M). Now, there are five hill districts in Manipur. Of these five hill districts, three, i.e. Ukhrul, Senapati and Tamenglong districts, the Naga population is in majority. Chandel is a mixed district. Though the Nagas are in majority, other population—the Kuki population and others belonging to other communities—is also considerable. So, NSCN has an evil eye of creating a South Nagaland consisting of all these four districts of which the Deputy Chief Minister, Shri Rishang Keishing is in active collusion.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Will you please wind up your speech?

SHRI W. KULABIDHU SINGH: That is the main trouble. The Governor anticipated that if these activities of the NSCN were not curbed, ultimately there would be a Meiteitribal conflict in Manipur in the near future and also inter-tribal conflict in Nagaland also. So, this sort of a situation is created by the so-called political leaders in our State.

Madam, about the source of arms, already about 3,000 arms received from outside India were recovered. Out of these 3,000 arms, some 200 are very sophisticated weapons which even our Security Forces do not posses. Even though our Army possesses such sophisticated weapons, our CRPF, State Police, etc., do not possess such sophisticated weapons. Only 300 weapons have been recovered. There are a lot of weapons in the hands of the insurgents there. I think, they have to be quickly recovered.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Will you please wind up?

AN HON. MEMBER: He is from Manipur. He may be allowed some more time.

SHRI W. KULABIDHU SINGH: Madam, regarding foreign assistance to these insurgents, the Governor has disclosed certain things in his Report. The Governor was the GOC, Eastern Command. He was mainly of the Manipur-Nagaland sector. He knows every nook and corner of Manipur and Nagaland, apart from the other Eastern parts. The Governor, in his report, mentioned, and I quote:

> "They have further strengthened their links with Meitei extremists, ULFA, HPC, Myanmar insurgents, and are actively supported by the DG Field Intelligence of Bangladesh and ISI of Pakistan."

So, foreign assistance is very much there in our region of Nagaland, Manipur, Mizoram and even Assam and other States. The situation is very tense. As I said earlier, it is not as difficult and complicated as in Kashmir. If a little attention is given by the Central Government, it can be solved, the insurgency can be curbed.

Madam, my friend has mentioned as to why the Assembly is kept under animated suspension. The common people of Manipur are fed up with the so-called popular Government which has no popular image. So, we do not know whether the Central Government is putting this under animated suspension because there are many floor-crossing MLAs. Some bait is being offered to these floor-crossing MLAs to join the Congress Party. That is the only motivation because the law and order situation does not warrant such a thing. Animated suspension means a bait to those opportunistic MLAs who want to join the Congress. In the Centre, the Congress Government is there. Only to offer a bait to these opportunistic MLAs, the Assembly has been kept under animated suspension. Therefore, Madam, I demand the immediate dissolution of the Assembly. It is a must because the common people of Manipur are fed up with any sort of a Government with the present MLAs. Of those 60 MLAs, many have crossed the floor three times and four times. The common people are fed up with these floor-crossing MLAs, and they will not allow any new Government to be formed by these floor-crossing MLAs. So, I want an immediate dissolution of the Assembly and a solution to the Kuki-Naga trouble. There should be an enlargement of powers for District Councils in those five hill districts of Manipur. Under the 72nd and 73rd Constitutional amendments, powers of the gram panchayats, powers of the municipalities and the corporations have been enlarged. Similarly, the spirit of the Sixth Schedule of the Constitution should be applied to the districts of Manipur so that more power could be entrusted with the District Councils.

These are my suggestions and I thank you again for the patient hearing given to me.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam Vice-Chairman, I do not rise here to urge the House not to vote for the Resolution because, as has been stated earlier, we, as a part of the Opposition, do not want to expose ourselves to the charge that we are taking a stand which will create a Constitutional void in the State of Manipur. But that does not mean that extension of the President's Rule should be thrust upon the Opposition as a *fait accompli* because there are fundamental issues involved and there are differences in the fundamental approach in tackling the problem.

We have stated time and again that the battle for national unity in the country cannot be fought by bullets alone. If we try to fight the divisive tendencies, fissiparous tendencies through the Central administrative fiat by using the security forces, the situation cannot be brought under control.

I draw the attention of the hon. Home Minister to the Supreme Court's verdict. The whole question of invoking article 356 has to be reviewed by the Central Government because invoking article 356 is also subject to judicial review. There are many questions vis-a-vis imposition of article 356 and the dissolution of the government. An hon. Member of the Janata Dal also referred to many questions about the background in which extremism and the ethnic clashes assumed such a proportion where the elected government had to be removed. The role of the Congress Party is there. There have been widespread press reports on the extent to which extremism went. One of the major factors influencing the events was the infighting within the Congress Party. The point is that we had

[Shri Nilotpal Basu]

to pay the price for it. Now the question is whether these things will stop or not. The question is whether after so many years after independence, the North-Eastern States cannot be integrated into the national mainstream. Why can't we have a political stability? Why extremism will have its writ running over the entire region? The Home Minister has observed that there is a definite improvement in the law and order situation. We are being reported day in and day out that new outfits are coming up in the region; new extremist outfits are coming up. In fact, the situation was a little bit looking up in Assam. But now there also, new developments and new activities of the terrorist outfit are taking place. Therefore, our point is that all these questions of terrorism, of ethnic diversity that is there in the region, and the question of democracy have to be given a fresh look. This is essentially a political problem and it has to be tackled at a political level. Issuing administrative fiat and removing an elected government by invoking article 356 does not solve the problem. Therefore, while extending our support—of course, it is a *fait accompli* for us—I think we should take this opportunity to really put our heads together to the problem so that we do not have to take up any such Resolution in future, in this House.

With these words, I conclude, Madam. Thank you.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मणिपुर की हालत दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है। ज्यों-ज्यों सरकार दवा कर रही है, त्यों-त्यों हालत खराब होती चली जा रही है। पिछली फरवरी में हमने मणिपुर के एक डेलीगेशन के साथ गृह मंत्री से मुलाकात की थी और बताया भी था कि वहां हालत बहुत ही खराब हो गयी है। पहले वहां कुकी और नागा लोगों में सघर्ष होता था, अब इधर मेती और मुस्लिम के बीच दंगा, जोकि पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ, वह भी होने लगा है। वहां बड़े पैमाने पर लोगों के पास हथियार हैं। वहां फॉरेन एजेंसियां काम कर रही हैं और बांग्लादेश में उन्हें कौन लोग ऑर्गनाइज कर रहे हैं, यह तो पता नहीं है, लेकिन उनके जरिए हथियार आ रहे हैं। बर्मा और भारत के बीच में जो जमीन है, वहां तो कोई मालिक ही नहीं है और काफी हथियार वहां से आ रहे हैं। रिपोर्ट तो यह है कि बांग्लादेश में यह सब पाकिस्तान के खुफिया विभाग आइ०एस०आइ० के जरिए भी ऑर्गनाइज करवाया जाता है। दूसरे वहां हमारी पुलिस के पास तो रायफल्स और बंदूकें है, लेकिन उससे ज्यादा सॉफिस्टीकेटेड हथियार उसके पास हैं जिनसे कि हमें लड़ना होता है क्योंकि वह आर्मी से हथियार लेकर लड़ते हैं। महोदया, हालत वहां यह हो गयी है कि वहां हमारी पुलिस, आसाम रायफल्स और सेना के हथियार की भी एक बार लूट हो गयी थी और वे हथियार अभी तक रिकवर नहीं किए जा सके हैं। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ? मैं भी एक बार वहां गया था और हमारे साथ डेलीगेशन के जो लोग आए थे, उनमें एक वहां की सी०पी०आई० के पहले मिनिस्टर भी थे। उनका कहना था कि वहां शाम के बाद निकलना कठिन है। हम लोग शाम के बाद निकल नहीं सकते। तो चारों तरफ हथियारबंद गैंगस्टर्स का ही राजपाट हो जाता है। गांवों में तो हमारा राज है ही नहीं। हम यह कहकर संतोष भले ही कर सकते हैं कि वहां हमारा राज है, लेकिन सच्ची बात यही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आपको कोई नयी पेशकदमी लेनी चाहिए।

गवर्नर को हमारी पार्टी ने पिछली 25 जनवरी को जो मेमोरेंडम दिया था, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि उसके सैलिएंट फिचर्स क्या हैं और जिस एसेंबली को आप अभी भी बरकरार रखना चाहते हैं उसका क्या हाल है?

> "The antecedents of the majority of the present M.L.As. are too well-known to be recalled."

यह एम०एल०ए० ऐसे है जोकि एक-न-एक हथियारबंद गिरोह से बंटे हुए हैं। वहां जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके बारे में भी और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनके बारे में भी यह सारी बातें आ गयी हैं कि गिरोह के साथ वे सरकारी पद पर रहकर उनकी सरकारी मदद करते हैं और उसी एसेंबली को आप रखे हुए हैं। इसलिए हमारा यह असेसमेंट है कि:

> "It is asserted that any permutation and combination of the existing M.L.As., to form a popular Government in manipur will only deteriorate further the overall situation in the State, be it in the sphere of law and order or of development or anything else. The

only way to a new hope is to dissolve the Manipur Legislative Assembly and to call for a fresh mandate of the people of Manipur at the earliest, through a humanly possible free and fair election."

अब इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

अब आप फिर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। हम इसके पक्ष में इसलिए नहीं हैं कि हमने तो आपको जनवरी में ही वार्न कर दिया था और फरवरी में भी मिलकर वार्न किया था और फिर भी आप कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन बढ़ा दें। तो हमें लग रहा है कि आप ऐसी तिकड़म में लगे हुए हैं कि किसी तरह से वहां अपनी पार्टी की सरकार बना लें। यह सब आपने किया है और कर के उसका नतीजा भी देख लिया है। कश्मीर और पंजाब में भी भुगत लिया है और अब यह नॉर्थ-ईस्ट भी उसी तरह से होता चला जा रहा है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप पार्टी के लेवल से ऊपर उठकर इस समस्या का निदान कीजिए नहीं तो इस देश को हम लोग बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं जिसके लिए मौजूदा पीढ़ी जिम्मेदार होगी और आपकी सरकार जिम्मेदार होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदया, समय नहीं है फिर भी मैं कहना चाहूंगा और हमने मेमोरेंडम में भी कहा था कि मिलिटेंटों से बात की जाये। अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम आपको लिस्ट ऑफ पर्सन्स दे सकते हैं, आप उन लोगों से बात कीजिए। उपद्रवी लोग जोकि वहां ऐसा कर रहे हैं और मिलीटेंट्स के साथ बातचीत करने की जरूरत है। सरकार को यह डिफरेंट लेवल पर इनीशिएट करना चाहिए, यह नहीं कि यहां से अनाउंस कर दें कि हम फलाने से बात कर रहे हैं। यह तो नहीं होता है, बात करने का कोई तरीका होता है। आपने देखा कि पेलिस्तीनियन और इजरायल वालों की कैसी बातचीत हुई? कैसा वहां हुआ? पता नहीं आप लोग कैसे बात करते हैं? कहीं से कोई नतीजा निकलता ही नहीं है। न कश्मीर का निकल रहा है, न इधर निकल रहा है।

दूसरा, हम लोग ऐसा फील करते हैं कि कम से कम एक टाइम-बाउण्ड, एक महीना या दो महीना यूनिलेटरल सीज फायर कर दें और उस दरमियान में बातचीत को और भी तेज कर दें। जो टी०डी० एक्ट है, आर्मड फोर्सेज स्पेशल प्रावर एक्ट है उसको फिलहाल, सब दिन के लिए नहीं, उसी पीरिएड के लिए आप रोक दीजिए और बोर्डर सील करने का इंतजाम कीजिए। जैसा में जानता हूं, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बोर्डर हमारा है, सील कोई दूसरा करेगा नहीं। अमरीका तो आकर नहीं कर देगा। इसीलिए इसका भी इंतजाम होना चाहिए और अगर हमारे पड़ोस के लोग तैयार हों तो ज्वायंट पेट्रोलिंग का भी हो सकता है।

मैडम, हम लोगों ने सुझाव दिया था, यह इलेक्शन करवाने के अलावा, कि वहां आल राउण्ड करप्शन है। मंत्री जी को यह याद होगा कि डिटेल्स में हम लोगों ने उन्हें बताया था कि कोई भी मदद आप देना चाहेंगे वह लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगी, कोई भी डवलपमेंट का काम उनका हो नहीं सकता। इसलिए इसका कोई रास्ता निकाला जाए और एक डवलमेंट प्रोग्राम बनाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहूंगा, चूंकि मैंने पहले ही आपको यह सुझाव दे दिया था, मैं अब इस एक्सटेंशन के पक्ष में नहीं हूं। जब तक आप यह न कहें कि यह तिकड़म करने के लिए एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं बल्कि इलेक्शन के लिए कर रहे हैं तब तक मैं राजी नहीं हो सकता और हम इसके लिए तैयार भी नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : बहुत बहुत धन्यवाद, मिश्रा जी। आपने काफी संक्षिप्त में कहा। श्री एस०पी० मालवीय।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपाध्यक्षा जी, यह जो संविधान का अनुच्छेद 356 है, इसके बारे में जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था—"It will remain a dead letter." लेकिन जैसा कि अभी मेरे विद्वान मित्र संघ प्रिय गौतम जी ने कहा कि 1952 से लेकर आज तक सौ बार इसका दुरूपयोग या प्रयोग हो चुका है।

श्री चतुरानन मिश्र : एक सौ बार के लिए और तैयार रहिए, जब तक आप और हम हैं यहां।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : और इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के संबंध में अनुच्छेद 356 पर एक फैसला दिया है और उस फैसले में कुछ गाइडलाइन भी तय की हैं। एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल केवल जनवरी, 1995 तक है तो उसको आप क्यों जिंदा रखे हुए हैं। बगैर चुनाव कराए वहां कोई दूसरा विकल्प है नहीं तो आप विधानसभा को क्यों निलंबित रखना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी का जो आंतरिक झगड़ा है, उसका समाधान करने के लिए आप संविधान का दुरुपयोग करना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

कि एक तो जो वर्तमान विधान सभा है, जिसके संबंध में काफी चर्चा इस सदन में आज भी की जा चुकी है उन सदस्यों के बारे में, उस विधानसभा को बिल्कुल आप भंग कर दीजिए और दूसरा आप घोषित करिए कि आप कब चुनाव कराने जा रहे हैं क्योंकि लोकप्रिय सरकार, जन-प्रतिनिधियों की सरकार के अलावा और कोई दूसरा विकल्प है नहीं।

महोदया, आपने अपने भाषण में यह कहा कि वहां की जो ला एण्ड आर्डर सिचुएशन है, जो कानून व्यवस्था है, उसमें सुधार हो रहा है। कानून व्यवस्था में सुधार होना एक अलग चीज है और कंस्टीट्यूशन मशीनरी ब्रेकडाऊन यदि होती है तो यह दूसरी चीज है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव वहां कराइए। मणिपुर राज्य हमारे देश का पूर्वोत्तर राज्य है, जो बहुत ही संवेदनशील राज्य है और इसलिए वहां के लोगों को आप मौका दीजिए कि वहां के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके, जो वहां की विधानसभा 60 सदस्यों की है, उसमें अपने प्रतिनिधियों को भेजे।

मेरा केवल एक यही सुझाव है, जैसा मिश्रा जी ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है, कम्यूनिस्ट पार्टी का मैमोरेंडम जो दिया गया उसमें भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था, कि यदि आप यह घोषणा करते हैं कि आप कब चुनाव कराने जा रहे हैं, उसकी कोई निश्चित तारीख अभी आप घोषित करें, निश्चित माह की घोषणा करें तो हम लोग सोच सकते हैं कि आपके प्रस्ताव का हम समर्थन करें अन्यथा हम प्रस्ताव का विरोध करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार समाप्त करूंगा इस आशा और विश्वास के साथ कि आप वहां की विधानसभा भंग करेंगे और नई विधानसभा के चुनाव कराने की तिथियों को घोषित करेंगे।

7 P.M.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): Madam Vice-Chairman, I must express my gratitude to all the hon. Members who mostly supported the extension of President's rule in Manipur, maybe for different reasons and having some reservations also in mind.

I was rather amused when Mr. Satya Prakash Malaviya himself said that Article 356 of the Constitution was invoked so many times and that it had been misused. At least I never thought that Mr. Malaviya would refer to this kind of a thing because he himself was also partly responsible for the imposition of President's rule and for no reasons whatsoever, but, at any rate, this is not the kind of debate which I would like to enter into now.

The situation in Manipur, and for that matter even in the entire North-Eastern region is, in fact, not very satisfactory. It will not be honest on my part to say that it is only in Manipur that things are not in good shape and that in the rest of the area things are very good. It will be a very big and a very tall claim on my behalf, and that is why, especially in the context of the influx of a large number of illegal migrants from across the border, I have to say that I am not particularly happy about the situation as it is prevailing in that area. The entire demographic picture of the entire region has also undergone a tremendous change. That is why it has become really a very serious problem, if not for anything else, at least because the local people feel it. After all, we have certain stakes in this land. We would like to have complete control over it. We have been reduced to minority, and those who have come as illegal migrants, have become the majority. This is the kind of situation in which they are. These are small matters of discontent which are being exploited by all those who are, in fact, very much interested in creating discontent and also a situation of destabilisation in our country. Most of our friends must be aware that they have some political motive. They have been supported by outside agencies. The ISI has been having plenty of money. Fortunately, if what has been reported in today's newspapers is correct, I am sure that now even the State Department of the USA for the first time has admitted that Pakistan's ISI is very much involved in creating destabilisation conditions.

श्री चतुरानन मिश्र: अब तो प्रधान मंत्री जा रहे हैं, अथेंटिक रिपोर्ट मंगा लीजिए।

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, that clearly shows the extent of interest the ISI has been taking in training the people and giving them funds and also in bringing all insurgent groups and terrorist groups together in order to see that they should not lose heart and that they should carry on this kind of activity. On the Kashmir front now they are not very strong, and that is why they would like to have some kind of a morale booster from other areas. So, they are spending a huge amount of money.

That apart, in Manipur, unfortunately, this situation has been imposed. This might be one of the few examples that we have in the history of imposition of President's rule. Though at the Centre we have the Congress (I) party in power, we have dismissed the Government of our own party in Manipur and for very valid reasons. In fact, that goes to show that we are not making any kind of distinction between a Congress government and a non-Congress government. I am sure that one of the lessons that the Members from that area will definitely learn is that whosoever tries to take law into his hands, tries to build some kind of connection with the underground elements and tries to create some kind of a vested interest in continuing the situation as it is prevailing in that area, even if it be the party in power, will not be spared.

At least I can give an assurance on the floor of the House that we are not interested in having any kind of horse-trading. We are not interested in forming some kind of a Government in that area, so long as we are not satisfied that it can be run on proper lines by some genuine people. There is nothing secret in this that I will be divulging if I say that in some of the areas in the North-Eastern Region, the Government of India has been providing not only developmental funds but also non-Plan funds.

I have my own doubts whether the entire money which is being provided by us is reaching the targeted groups or not. That is why we would like to start with Manipur. I have already given instructions to the Governor, his Advisers and all other officers that we should make a beginning from Manipur. We would like to see that all the money which has been given to them reaches the targeted group to have water supply schemes in that area, to have drainage schemes in that area, to have small irrigation projects in that area, to have electricity supply to all those people who, in fact, have not seen electricity so far, to create employment opportunities in that area so that the insurgents are not able to divert the minds of these young people for which moneys are being offered by the people across the border. I am sure if all these activities are taken up together and if greater emphasis is laid on finding solutions to the genuine problems of the people and if these problems are attended to properly, I see no reason why these people should lag behind and should be different from the rest of India. In fact, that is also one of the reasons why some of the people feel neglected. Of course, now we will have to think in terms of giving priorities in all fields where the Government of India is concerned. For example, laying of railway lines will have to be taken up in that area, construction of national highways will have to be taken up in that area, construction of airports will have to be taken up in that area so that at least the main capital cities are connected somehow or other by one method or other.

श्री चतुरानन मिश्र: आपने डेवलपमेंट की बात कही। अच्छी कही। मैंने डेडीकेशन के साथ आपसे अनुरोध किया था कि हमारे मणिपुर के लोग स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं। इसलिए स्टेडियम बनाने की बात उन लोगों ने आपसे कही थी। आपने भी कहा कि सिम्पैथेटिकली विचार करेंगे। क्या उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई?

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Minister, you were referring to the strengthening of infrastructure in the North-Eastern Region. I will just give

[Shri Nilotpal Basu]

you one instance. Earlier 14 flights were operating between Calcutta and Agartala. Now, all of a suden, without giving any reason, the Government has slashed down the number of flights from 14 to 9 and that too on most of the days they are cancelled. This is the kind of increased and reinforced treatment that you are giving to that region.

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, I am sure that the hon. Member must be aware of the fact that the Civil Aviation Minister had gone to that area specially and after meeting all the Chief Ministers there, he has announced that these flights are going to be restarted; and the entire area is going to be covered. So road, rail and air links are going to be available in that area. But it will take sometime to complete the entire thing. But there is no denying the fact that efforts are being made to lay special emphasis on the development of that area so that the people may not have the feeling of being neglected. That is the only thing which I am trying to emphasise. Unfortunately, there was no accounting system as such. There is no financial discipline in that area. That is why we propose to make a beginning from Manipur. We will have Special Officers and see that financial discipline is imposed in that area and that every pie is properly accounted for and the money which is meant for a particular group of people reaches them. These are the three things which we have in view. Officers, who will be having some aptitude for development, will be specially selected for being sent to those areas. I am sure, with this kind of approach, it should be possible to change the entire atmosphere. At least the people will begin to compare. They will think, "When this thing can happen under President's rule, why is it that under the popular rule it is not possible for us to do the same kind of thing?". It is bound to create this kind of a feeling and make them draw comparisons. And that is why I feel that this is the only good approach. After all, power is always available to us. I have the figures as to how many companies we have sent. I am not so much interested in giving you the figures. If by any chance, inspite of all these efforts that we have made, we do not succeed, ultimately, for curbing the insurgency or the terrorist activity, the power of the State is always available and can be utilised for crushing them. But it is not only force which can work. All the development activities will have to be given priority. Let us win the hearts of the people and, thereafter, if they misbehave, then, of course, we have the machinery of the Government also which we can, possible, utilise for that purpose. I do not think that I need elucidate any other point.

I can merely say that, in the matter of imposition of President's rule in a particular area, after the Supreme Court judgement, we will definitely take more care. But I must also say that unless we are satisfied that the State is not being run according to the provisions of the Constitution, normally, we do not take the step of imposition of President's rule.

श्री चतुरानन मिश्र: ऐसेंबली को डिजाल्व कर दीजिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : ऐसेंबली को डिजाल्व कभी भी कर सकते हैं, उस में कोई प्राबलम नहीं है। आज करने के बजाय हो सकता है कुछ क्वूहात हों जिन के कारण हम उन को रखना चाहते हैं, लेकिन

I do not want to give the impression as if we are interested in horse-trading and again, interested in forming the Government in that area. I am prepared to give that kind of an assurance to the House. I think that with this explanation, the hon. Members will agree to the resolution which I have moved.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) : Mr. Satya Prakash Malaviya, are you going to withdraw your amendment?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : No, Madam. I am pressing for it.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS

SAROJ KHAPARDE) : Now, I shall first put the amendment moved by Shri Satya Prakash Malaviya to vote.

The question is :

"That in the said Resolution, *for* the words "six months", the words "three months" be *substituted.*"

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) : I shall now put the Resolution to vote.

The question is :

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 31st December, 1993, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Manipur, for a further period of six months with effect from the 30th June, 1994."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) : Now, there are some Bills. I think we should take them up today itself.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : Madam, now the House may be adjourned.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) : These Bills are very small Bills and are non-controversial. You can finish them today itself. (*Interruptions*). Will you extend your cooperation?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, please adjourn the House. This can be taken up as the first item after the Question Hour tomorrow. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I would like to say that these two Bills are absolutely non-controversial. (*Interruptions*).

SOME HON'BLE MEMBERS: Please adjourn the House.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Let the Secretary-General read out the message from the Lok Sabha.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Rubber (Amendment) Bill, 1994

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Rubber (Amendment) Bill, 1994, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 10th May, 1994.
>
> 2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Madam, I lay a copy of the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Wednesday.

The House then adjourned at seventeen minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 11th May, 1994.

MGIPCBE-CRC-3 RSS/ND/96-26-6-96-400 Copies